

पर्यावरणवाद व पर्यावरणीय आन्दोलन : एक लोकतंत्रिक प्रयास



पूजा सिंह
शोध छात्रा
राजनीति विज्ञान विभाग
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय
वाराणसी।

यद्यपि पर्यावरण से जुड़े सरोकारों का लम्बा इतिहास है लेकिन आर्थिक विकास के कारण पर्यावरण पर होने वाले असर की चिंता ने 1960 के बाद से राजनीतिक चरित्र ग्रहण किया। पर्यावरणवाद का सम्बन्ध मुख्यतः 1960 एवं 1970 के दशक के पर्यावरण आंदोलनों से है। 1960 के दशक में रैचल कारसन की साइलेंट स्प्रिंग, ऐरालिन की जेम च्वचनसंजपवद ठवउड़ तथा गैरट हारडीन की ज्तहमकल वजिम ब्यउउवदे नामक पुस्तकों के प्रकाशन से बढ़ती आबादी एवं पर्यावरण विनाश के प्रति दुनिया का ध्यान आकर्षित हुआ।¹ पर्यावरणवाद के आरंभिक संकेत म्ण्ण शूमेकर की कृति 'उंसस पे ठमंनजपनिस'; 1973 के अन्तर्गत मिलता है, शूमेकर ने लिखा है कि वर्तमान समाज जिस नींव पर खड़ा है उसे खोद रहा है। वैश्विक मामलों से सरोकार रखने वाले एक विद्वत् समूह 'क्लब आफरोम' ने 1972 में 'स्पउपजे ळतवूजी' शीर्षक से पुस्तक प्रकाशित की जिसमें बढ़ती आबादी के आलोक में प्राकृतिक संसाधनों के विनाश के आदेशों को बखूबी उठाया गया। इन प्रयासों से बढ़ती आबादी तथा पर्यावरण क्षय व उसकी भयावह तस्वीर ने हरित आन्दोलनों को प्रेरित किया।²

हरित आन्दोलन 1970 के आरम्भ में नवगमवाद से प्रारम्भ हुआ। नवीन वामवादियों ने पूँजीवाद व समाजवाद द्वारा अपनाये जा रहे औद्योगीकरण व बड़े संगठनों की भूमिका खारिज करते हुए कम्यूनो में रहने का विकल्प दिया। नववायवाद के उत्तरार्द्ध में महिलावादियों ने पर्यावरण के क्षय को पुरुष प्रभुत्व सामाजिक व्यवस्था से जोड़कर हरित आन्दोलनों का समर्थन किया।

पर्यावरण की दिशा में न्यूजीलैण्ड, आस्ट्रेलिया, यूके व पश्चिमी जर्मनी में राजनीतिक दलों ने विशेष प्रयास किये। 1972 में न्यूजीलैण्ड में पहली हरित पार्टी टंसनम च्तजल के नाम से अस्तित्व में आयी, तदोपरान्त ब्रिटेन व अन्य यूरोपीय मुल्कों में ग्रीन पार्टियों का गठन हुआ और वहां की संसदों में ग्रीन सांसदों की उपस्थिति दर्ज हुई।

सभी राजनीतिक विचारधाराओं में हरितवाद नवीनतम है किन्तु उसकी जड़े प्राचीन हैं। प्रकृति और मानव का तादात्म्य, पश्चिमी औद्योगिक सभ्यता के उदय के पूर्व तक कायम रहा। उपभोक्तावादी-पूँजीवादी अन्धी दौड़ ने प्रकृति पर विजय को ध्येय बनाकर सभ्यता को विकास के नाम पर विनाश तक पहुँचा दिया। डलरिच बैंज अपनी पुस्तक 'टो'वबपमजल में वर्तमान समाज को खतरनाक समाज कहता है जहां पर्यावरण का विस्फोट कभी भी हो सकता है। व छमपसस पर्यावरण क्षय को वैश्वीकरण का सत्रांस कहता है।

हरितवाद एक नया धर्म है, जिसमें तीन तरह के लोग शामिल हैं। प्रथम श्रेणी के लोग पृथ्वी को देवी मानते हैं तथा स्वयं को उसके अनुरूप ढालने के समर्थक हैं। द्वितीय श्रेणी में लोग प्रकृति के प्रेमी व पुजारी हैं परन्तु मानव प्रकृति सम्बन्ध में आध्यात्मिकता नहीं देखने तथा तृतीय श्रेणी उन लोगों की है जो भावुकता से हटकर खुद को पर्यावरण विज्ञान से जोड़ते हैं।⁴

हरित आन्दोलन की अनेक धारायें व उपधारायें हैं— मार्क्सवादी पूंजीवाद को पर्यावरण का शत्रु मानते हैं। महिलावादी पुरुष आक्रामकता को इस समस्या हेतु जिम्मेदार मानते हैं। अराजकतावादी और गाँधीवादी प्रकृति व मनुष्य के तादात्म्य के समर्थक हैं और छोटे-छोटे सामुदायिक जीवन को इसके लिये उपयुक्त मानते हैं।⁵

राजनीतिक विचारधारा के रूप में पर्यावरणवाद अभी निर्माण की प्रक्रिया में है। दार्शनिक व राजनीतिक दृष्टि से इसकी दो प्रवृत्तियाँ स्पष्ट दिखाई देती हैं— पहली शाखा मानव केन्द्रित है जिसे स्पहीज (दजीतवचवबमदजतपेज) कहा जाता है, इनकी नजर में प्रकृति का जो भी मूल्य है उसका मापदण्ड मानव है। पर्यावरण को बनाये रखने का इनका अनुरोध मानव जाति के नाम और उसके संरक्षण के लिये है। दूसरी शाखा जीव केन्द्रित है जिसे उपवबमदजतपब या म्बवबमदजतपब नाम से जाना जाता है। इस शाखा की नजर में मनुष्य प्रकृति का भाग है, धरती जीवित प्राणी है और मनुष्य तभी तक जीवित रहेगा तब तक कि पृथ्वी का जीवन है। इस शाखा में जो लोग आदिम कालीन पर्यावरण की बहाली चाहते हैं उन्हें कमच म्बवसवहपेज तथा जो प्रकृति में सुधार चाहते हैं उन्हें ससवू म्बवसवहपेज कहा जाता है।

उपवध्म्बव.बमदजतपब शाखा सामाजिक मूल्यों में आमूल परिवर्तन लाना चाहती है तथा एक ऐसे वैज्ञानिक समुदाय का निर्माण करना चाहती है जो वैकल्पिक तकनीकी तथा जीव क्षेत्रों (उपव.तमहपवदे) पर आधारित हो। हरितवादी दृष्टिकोण उपव.बमदजतपब है जिसकी मान्यतायें निम्नलिखित हैं—

- मानव प्रकृति का भाग है उसे प्रकृति के साथ ही जीना है नाकि नष्ट होना है।
- पृथ्वी के सीमित संसाधनों व जैविक पर्यावरण को बचाना जरूरी है।
- इसके लिए अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा के बजाय सहयोग जरूरी है।
- औद्योगिक विकास व जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण आवश्यक है।
- पर्यावरण संरक्षण हेतु भौतिक की अपेक्षा आध्यात्मिक एवं नैतिक मूल्यों को अधिक उचित स्थान देना जरूरी है।
- हरितवादी धन एवं शक्ति सकेन्द्रण के विरोधी हैं तथा सामाजिक न्याय चाहते हैं।
- हरितवादी अमीरों-गरीबों, प्रदेशों, क्षेत्रों, महाद्वीपों व पीढ़ियों के मध्य संतुलन चाहते हैं।

हरितवादियों का समाज म्बवजवचपं (पर्यादर्शलोक) होगा जो स्थानीय आत्मनिर्भरता पर आधारित छोटे-छोटे समुदायों से निर्मित प्रत्यक्ष प्रजातंत्र, वाला होगा लघुस्तरीय, जैविक खेती वाली, हस्तकलात्मक,

अर्थात् श्रम प्रधान, लघुउद्योगीय सहकारिता आधारित होगी जिसमें अनिरन्तर छवद त्मबलबंसपब संसाधनों का न्यूनतम प्रयोग किया जायेगा।

पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से विचारकों के दो वर्ग हैं— प्रथम कट्टर पर्यावरणवादी जो प्रकृति के साथ किसी छेड़छाड़ को अनुचित मानते हैं। द्वितीय सयंत या मुख्यधारा के पर्यावरणवादी जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी आदि का प्रयोग कर पर्यावरण की संरक्षण की बात करते हैं। पर्यावरणवाद जीवन की गुणवत्ता को आर्थिक संवृद्धि से अधिक महत्व देता है और प्राकृतिक संसाधनों, प्राकृतिक सौन्दर्य, वातावरण की स्वच्छता तथा नगरों एवं उपनगरों के स्वरूप को कायम रखने पर बल देता है। इन सब उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राजनीतिक नीति व कार्यक्रम तथा उपर्युक्त कानून के निर्माण हेतु सरकार पर दबाव डालता है।

पर्यावरणवाद एक तरफ प्रकृति एवं मनुष्य के टूटे संबंधों को फिर से जोड़ना चाहता है, दूसरी तरफ मनुष्य के सामाजिक राजनीतिक जीवन को नये रूप में ढालना चाहता है जिसमें स्वालंबिनीयता, छोटी-छोटी वस्तुओं अथवा संगठनों की गुणवत्ता, जनसंख्या नियंत्रण, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व, आध्यात्मिक पुनर्जागरण तथा प्रकृति के साथ जीने की कला जैसे गुणों को अपनाने पर बल दिया जाता है।

पर्यावरण से जुड़ा एक बहुचर्चित शब्द है पोषणीय अथवा धारणीय अथवा सतत विकास की परिकल्पना। इस शब्द का प्रथम प्रयोग 1970 में पर्यावरण और विकास पर कोकोयाक घोषणा के समय किया गया। परन्तु यह शब्द विश्व पर्यावरण एवं विकास आयोग के अध्यक्ष ब्रटलैंड द्वारा 1987 में प्रकाशित ज्ञत बवउउवद निजनतम रिपोर्ट के माध्यम से बहुचर्चित हुआ। इसमें कहा गया कि संसार में प्राकृतिक संसाधनों का असीम भण्डार नहीं है अतएव वर्तमान पीढ़ी को अपनी आवश्यकतायें इस ढंग से पूरी करनी चाहिए कि भावी पीढ़िया अपनी आवश्यकतायें पूरी करने में असमर्थ न हो जाये। सतत् विकास की दो धारणायें⁶ हैं—

डंगपउनउ'नेजंपदंड्सम'वबपमजल. यह एक ऐसे समाज की कल्पना है जो पर्यावरण के साथ संतुलन बनाये रखना चाहती है परन्तु सैद्धान्तिक सतर पर व्यक्ति का प्रकृति पर प्रभुत्व तथा भौतिक व अन्य आवश्यकताओं की प्राथमिकता को मौलिक मानकर चलती है। पर्यावरण की मानव केन्द्रित धारा इससे जुड़ी है।

अधिकतम संमोषित समाज राष्ट्र राज्यों के वर्तमान राजनीतिक—कानूनी, ढांचे में छिट—पुट परिवर्तन को सतत् विकास की आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिये पर्याप्त मानता है। पर्यावरण अनुकूल उत्पादों का निर्माण बाजार व्यवस्था द्वारा किया जा सकता है। रिसाइक्लिंग, साफ टेक्नोलाजी, वैकल्पिक ऊर्जा, पर्यावरण संबंधी कानून आदि की भूमिका के आख्या से बाजार व्यवस्था द्वारा सतत् विकास को पाया जा सकता है। इसे म्बव.ब्चपजंसपेउ अथवा छमू'हम ब्चपजंसपेउ का नाम दिया जाता है।

थ्तनहंस'नेजंपदंड्सम'वबपमजल. मिताहारी सपोषित क्षमा, के समर्थक कममच.म्बवसवहपेजे है। यह धारणा उत्पादन, उपयोग, राजनीतिक ढांचा, रहन—सहन और आदत में आमूल परिवर्तन की मांग करते हैं इसके तीन मूल—मंत्र हैं— मितहारिता, आत्मनिर्भरता तथा स्वेच्छिक सादगी। यह विकेन्द्रित सामुदायिक जीवन का समर्थक है जिसमें आवश्यकताओं को न्यूनतम कर दिया गया है।

मिताहारी संपोषित समाज की धारण राज्यों व उनके प्रान्तों का पुनर्गठन करना चाहती है एवं इसके लिए उपव त्महपवदे का सुझाव देती है। उपव त्महपवद एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें पर्वत श्रृंखलाएं, नदियां, पेड़-पौधों, मौसम, मिट्टी और जीव-जन्तुओं के मध्य सामंजस्य हो। न्यूनतम आवश्यकता वाली विकेंद्रित सामुदायिक जीवन पर आधारित प्रणाली को राबर्टसन^६ अर्थव्यवस्था नाम देता है यहाँ^६ का तात्पर्य है।^६ उम भनउंद म्बवसवहपबंस इस व्यवस्था में विनाशक तकनीकी का स्थान मानवीय हित की तकनीकी ले लेगी।

हरमन डेली ने मिताहारी संपोषित समाज की संकल्पना को राज्य अर्थव्यवस्था (जमंकल जंजम मबवदवउल) नाम दिया है जिसमें आने वाले दशकों में औद्योगिक अर्थव्यवस्था में परिवर्तन आवश्यक होगा। क्योंकि सीमित संसार में असीमित उत्पादन संभव नहीं है। संपोषित विकास के कुछ समर्थक औद्योगिक पूर्व समाज के तौर तरीकों की ओर लौट जाना चाहते हैं लेकिन कुछ केवल द्वितीयक आवश्यकताओं पर प्राथमिक आवश्यकताओं को वरीयता देना चाहते हैं।

पर्यावरण को बचाने के कुछ अमानवीय विचार भी प्रस्तुत किये गये हैं। गैरेट हार्डिन 1981 में प्रकाशित अपने एक लेख में लिखता है कि 'यह धरती असंख्य लोगों का बोझ नहीं, ढो सकती है। दुनिया के गरीब देश अपनी बढ़ती आबादी हेतु संसाधनों के पुनर्वितरण की मांग कर रहे हैं। वर्तमान परिस्थितियों में निर्धनता को बाँटा जा सकता है, सम्पन्नता को नहीं। अतएव सभ्यता की नैय्या बचाने के लिये इसके अतिरिक्त बोझ को समुद्र में फेंक देना चाहिए।

पर्यावरण संरक्षण के लिए किये गये प्रयास—

पर्यावरण की दिशा में पहला सशक्त प्रयास 1972 (5 जून 16 जून) का स्टाकहोम घोषणापत्र (पर्यावरण सम्मेलन) को माना जा सकता है जिसे प्रथम पृथ्वी सम्मेलन कहा जाता है और उसकी घोषणा को पर्यावरण का मैग्नाकार्ट नाम दिया जाता है। इसकी सिफारिशों के आधार पर दिसम्बर 1972 में महासभा ने यू0एन0ई0पी0 अथवा संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का गठन किया जिसे पर्यावरण संरक्षण का दायित्व सौंपा गया। इस पृथ्वी सम्मेलन में एक ही पृथ्वी सिद्धान्त को मान्यता दी गई। समस्याओं की पहचान हेतु। द मंतजी जबी च्त्वहतउउम पर्यावरण हेतु शिक्षा एवं प्रशिक्षण को प्रोत्साहन, पर्यावरण कार्यक्रमों हेतु स्वैच्छिक कोश तथा जागरूकता हेतु 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाये गये।⁷

न्छ ने न्छन् के संबंध में एक 58 सदस्यीय प्रशासकीय परिषद की स्थापना की। शासी परिषद ने पर्यावरण कार्यक्रमों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। 1976 के अपने हैवीटार सम्मेलन में शासी परिषद ने राज्यों से जैवमण्डल और महासागरों को प्रदूषण से बचाने की अपील की। स्टाकहोम सम्मेलन से यू0एन0 पर्यावरण कार्यक्रम की शुरुआत मानी जाती है जिसका मुख्यालय नैराबी में बनाया गया है।

जलवायु पर प्रथम विश्व स्तरीय सम्मेलन 1979 में जिनेवा में आयोजित किया गया। जलवायु परिवर्तन हेतु एक मुख्य कारक ओजोन क्षरण को रोकने हेतु अनेक प्रयास किये गये हैं⁸ यथा—

1. ओजोन परतसंरक्षण पर वियना अभिसमय 1985

2. ओजोन परत संरक्षण पर मांट्रियल प्रोटोकाल—1987
(ओजोन के क्षरण हेतु जिम्मेदार पदार्थों के उत्पादन पर पाबंदी लगाना। 1998 तक 50 प्रतिशत सीओएफओसीओ में कटौती)
3. आजोन परत पर हेलास की घोषणा 1989
(2000 तक सीओएफओसीओ का उत्पादन अवश्य कम कर दिया जाय तथा विकासशील देशों की परिलब्धियों का ध्यान रखा जाय)
4. सीओएफओसीओ पर लंदन सम्मेलन 1990
(उत्पादन एवं उपभोग की समाप्ति—2000 तक विकसित देश तथा 2010 तक विकासशील देश लक्ष्य पूरा करें)
5. सीओएफओसीओ पर कोपनहेगन सम्मेलन 1992
(सीओएफओसीओ की 1996 तक समाप्ति, हाइड्रो फ्लोरोकार्बन की 2010 तक समाप्ति।

विकासशील देशों में पर्यावरण की विगड़ती स्थिति के कारण पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग (स्म्व) का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष ब्रण्टलैण्ड ने 1987 में अपने जल ब्युत्पन्न जनतम त्मचवतज में संपोषित विकास पर जोर दिया। इस रिपोर्ट में उठाये गये मुद्दों पर विचार करने हेतु द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन रियो—डी—जेनेरियो (ब्राजील जून 1992) में आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में बसपउंजम बींदहम तथा टपवकपअमतेपजल पर सहमति त।यार की गयी। बसपउंजम बींदहम बवदअमदजपवद 1993 तथा टपवकपअमतेपजल बवदअमदजपवद 1894 से लागू किया गया है। पृथ्वी सम्मेलन को उसके सचिव मारिस स्ट्रांग ने च्त्सपउंमदज व्त्संदमज का नाम दिया। द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन में रियो घोषणा के अतिरिक्त।हमदकं 21 का निर्धारण किया गया जिसमें 21 प्रमुख मुद्दों पर जोर दिया गया जिसमें धारणीय विकास के बारे में एक व्यापक कार्ययोजना को आकार दिया गया। रियो सम्मेलन में वन सिद्धान्त कथन को विशेष महत्व दिया गया ताकि पर्यावरण संरक्षण हो सके।

रियो सम्मेलन के बाद 1990 में बसपउंजम बींदहम च्त्वजवबंस ब्यूनेस आयर्स तथा 2000 में बसपउंजम बींदहम बवदअमदजपवद हेग में आयोजित किया गया। वन सिद्धान्त के कार्यान्वयन हेतु नई दिल्ली में 1983 में एक मंत्रिस्तरीय सम्मेलन का आयोजन हुआ जिसे विकासशील हेतु वन मंच के नाम से जाना जाता है। 1993 में पोषणीय विकास हेतु एक 53 सदस्यीय पोषणीय विकास आयोग का गठन किया गया जो कार्यरत है। रियो सम्मेलन एवं उसकी उद्घोषणाओं की समीक्षा हेतु न्यूयार्क में 1997 में पृथ्वी शिखर +5 सम्मेलन महासभा द्वारा आयोजित किया गया।

न्छम् द्वारा 1996 में हैवीटेट सम्मेलन (सिटी सम्मेलन) तुर्की में आयोजित किया गया जिसमें भंडपजमज।हमदकं स्वीकार किया गया। इस एजेण्डे में 21वीं सदी के पहले दो दशकों में विश्व के सभी गाँवों व शहरों के समुचित विकास के लिये मार्गदर्शन व कार्यवाही की अपेक्षा की गई।

संयुक्त राष्ट्र के जलवायु परिवर्तन सम्मेलन (नूथल्ल) द्वारा 1997 में लसवइसमँतउपदह पर एक सम्मेलन जापान के क्योटो शहर में आयोजित किया गया जिसमें एक प्रोटोकाल स्वीकार हुआ। इस प्रोटोकाल को 16 फरवरी 2005 से लागू किया गया है। 1990 को आधार वर्ष मानकर 6 प्रतिशत ग्रीन हाउस गैसें यथा— नाइट्रस आक्साइड मिथेन, हाइड्रोफ्लूरो कार्बन, CO_2 , क्लोरो फ्लोरोकार्बन तथा सल्फर हेक्सा फ्लोराइड के उत्सर्जन में 5.2 प्रतिशत कमी लाना है। 21 देशों हेतु लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं जिसमें यूरोपीय संघ 8 प्रतिशत, अमेरिका 7 प्रतिशत, जापान 6 प्रतिशत की कमी करेगा। इस लक्ष्य को 2008 से 2012 तक पूरा कर लेना है। इसमें 36 औद्योगिक देशों पर विशेष जिम्मेदारी सौंपी गयी है। भारत, चीन जैसे विकासशील देशों को इस मामले में छूट प्रदान की गई है। दिसम्बर 2007 में आस्ट्रेलिया के हस्ताक्षर कर देने के बाद नै। एक मात्र औद्योगिक देश है जसने प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर नहीं किया है। प्रोटोकाल में यह भी कहा गया है कि विकसित देश विकासशील देशों को जलवायु संबंधी अध्ययनों व प्रोजेक्टों हेतु जानकारी व प्रौद्योगिकी मुहैया कराये। अगस्त 2002 में तीसरा पृथ्वी सम्मेलन जोहान्सबर्ग में आयोजित किया गया जिसमें संसार के सबसे बड़े प्रदूषक अमेरिका की भागेदारी नहीं थी। सम्मेलन के उपरान्त की गई घोषणा में निम्नलिखित बातें महत्वपूर्ण थी⁹—

- 2015 तक दो बिलियन लोगों को पीने योग्य जल उपलब्ध कराने की कार्ययोजना का निर्माण
- पुनर्प्रयोज्य ईंधन के प्रयोग को बढ़ाने पर जोर तथा जीवाश्म ईंधन (कोयला, पेट्रोलियम एवं गैस) के प्रयोग में कमी।
- पर्यावरण संरक्षण में विकासशील देशों को और अधिक सहायता।
- प्राणियों एवं वनस्पतियों की दुर्लभ प्रजातियों की विलुप्ति दर में 2010 तक पर्याप्त कमी लाना।
- 2020 तक खतरनाक रसायनों का उत्पादन इस प्रकार सुनिश्चित करना ताकि मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण पर बुरा असर न पड़े।
- 2004 तक जैव विविधता नुकसान को कम करना।
- 2010 तक विकासशील देशों को ओजोन परत के अनुकूल वैकल्पिक श्रोतों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। खतरनाक कचरे का स्वच्छ तरीके से निस्तारण करना।
- 2004 में खतरनाक कीटनाशकों एवं विषैले रसायनों आदि पर प्रतिबंध लगाने वाले स्टाकहोम संधि प्रभावी हो गई है।
- इसके साथ-साथ अभी हाल में पेरिस जलवायु समझौता सम्पन्न हुआ जिसमें नूथल्ल के माध्यम से ग्रीनहाउस गैस को समाप्त करना है। इसमें 2100 तक औद्योगिकयुग से पहले की तुलना में ग्लोबल वार्मिंग को 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे सीमित करना है। इसमें कुछ विद्वानों ने इससे पहले ही 2050 तक ही यह लक्ष्य प्राप्त करने की बात को स्वीकारने की बात की और 2100 तक शून्य स्तर पर लाने की बात की।¹⁰

पर्यावरण के प्रति सचेतना में निःसंदेह वृद्धि हुई है लेकिन उसके निपटने में राजनीति की जा रही है। धनीमुल्क गरीब देशों के पर्यावरण पर ऐतिहासिक तर्क को खुले दिल से स्वीकार नहीं करने तथा अपने अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों से भाग रहे हैं। पर्यावरण पर आयोजित सम्मेलन उत्तर-दक्षिण विवाद का शिकार हो जा रहे हैं। पर्यावरण की संधियों को लागू करने में हीला-हवाली की जाती है। चूँकि पर्यावरण सबका इसलिये जिम्मेदारी सबकी है यह धनी मुल्कों का सूत्र है। गरीब मुल्कों का कथन है कि पर्यावरण साझा है परन्तु जिम्मेदारी अलग-अलग है क्योंकि जो प्रदूषक है वही जिम्मेदारी उठाये। इस वैश्विक स्थिति में जब विश्व को इस मसले पर विकसित देशों की उत्तरदायित्व को जरूरी समझा जा रहा है तो अमेरिका जैसे देश जलवायु समझौते से हटकर जलवायु समस्या की और कठिन बना दे रहा है। यदि उत्तरदायित्व आरोपण का यही सिलसिला चलता रहा तो मानवता का अन्त तय है।

इस समस्या का हल जो भी हो परन्तु पर्यावरणीय आन्दोलन व पर्यावरणवाद अध्ययन से जो प्रमुख बात सामने आती है वह यह है कि पर्यावरणीय आन्दोलन व विचार दोनों ने एक साथ चलना शुरू किया है। जिस तरीके से इसका ध्येय भी मानव भलाई है उसी तरीके से यह आन्दोलन भी अभी तक गैरहिंसात्मक व लोकतांत्रिक स्वरूप को लिए हुए रहा है। पर्यावरण वादी विचार भी अपने-अपने विचार लोकतांत्रिक तरीके से ही दिये हैं। अतः यही कहा जा सकता है कि पर्यावरणवाद व पर्यावरणीय आन्दोलन का स्वरूप लोकतांत्रिक पैमाने पर बिल्कुल खरा उतरता है।

सन्दर्भ सूची-

1. बिस्वाल तपन : अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध : मैकमिलन पब्लिशर्स इंडो प्राइम लिमिटेड नई दिल्ली।, 2012, पृष्ठ सं० 344।
2. भरुचा, इराक: पर्यावरण अध्ययन : ओरियंट ब्लैकज्वान, हैदराबाद, 2012, पृष्ठसं० 2012-13।
3. दधीचि नरेश: समसामयिक राजनीतिक सिद्धान्त की रूपरेखा; रावत पब्लिकेशन नई दिल्ली, 2015 पृष्ठसं० 170-182
4. गावा, ओपी०: राजनीतिक सिद्धान्तों की रूपरेखा; मयूरपेपरबैंक नोएडा, 2005, पृष्ठसं० 427-437।
5. गावा, ओपी०: राजनीतिक सिद्धान्तों की रूपरेखा; मयूरपेपरबैंक नोएडा, 2005, पृष्ठसं० 438-447।
6. हेडड, ऐण्ड्रयू : ग्लोबल पालिटिक्स : पालग्रेव मैकलिन 2010 पृष्ठसं० 390-418।
7. गुहा रामचन्द्र : आखिरी उदारवादी और अन्य निबन्ध-पेंगुइन बुक्स, नई दिल्ली, पृष्ठसं०-49-59
- 8- <https://en.m.wikipedia.org/wiki/united-Nations-climat-change- confence>.
9. UN/DESA September 2002
10. IPCC: Greenhouse gas imissions acceler4ate despite reduction efforts UN Climate panel 14, April 2014.